

प्रेषक,

आर० डी० पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानियन्त्रक,
मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
देवीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 24 जनवरी, 2008

विषय- वण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 10 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-154 / xiii-e-1/2008 Admin.A, दिनांक 11-01-08 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल 10 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों का कार्यकाज शासनादेश संख्या-47 / XXXvi(1)/2007, दिनांक 26 फरवरी, 2007 के क्रम में दिनांक 01-03-08 से दिनांक 28-02-09 तक अथवा नियमित नियुक्ति जो भी पहले हो, वशर्त कि वे पद उसके पूर्व दिना किसी पूर्ण सूचना को समाप्त न कर दिये जायें, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला खय आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 की आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतार-105-सिविल और सेन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1252 / वित्त अनुभाग-5 / 2008, दिनांक 22-01-08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर० डी० पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : ११ / XXXvi(1) / 2008 तदुदिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- समस्त जिला न्यायाधीश / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 3- कार्मिक / नियुक्ति, अनुभाग / वित्त अनुभाग-5 ।
- 4- एन.आई.सी. / गार्ड फाईल ।

आह्वय

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।